पास सहायता के लिए भेजती हैं। परन्तु, सहायता देने के बजाय बैंक उनको अपनी तरफ से छानबीन करने के लिए बराबर दौड़ाते रहते हैं और फिर भी सहायता नहीं देते। ऐसी दोहरी व्यवस्था के कारण अधिकतर चयनित परिवार सहायता पाने से वंचित ही रहते है और दूसरी तरफ उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के सरकारी कार्यक्रम की सफलता में तब तक शंका बनी रहेगी जब तक कि बैंक इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग नहीं करेंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि राज्य सरकारों द्वारा एक सीमित रकम तक दी गई सहायता की जमानत लेने के बावजूद भी बैंक सहायता देने में आनाकानी कर रहे हैं।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस कार्य को देखने के लिए प्रत्येक जिले में एक सलाहकार समिति बनायी जाए जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता पाने वालों को बैंक से सहायता दिलाने के काम में मदद करे।

**(viii) Running Sarnath Express train daily between Varansi and Durg.**

**श्री बी०डी० सिंह** (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी एवं दुर्ग नगरों के बीच चलती है। वाराणसी से यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन वृहस्पतिवार एव शनिवार को चलती है और उसी प्रकार दुर्ग से सप्ताह में दो दिन शुक्रवार एवं रविवार को चलती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार के दसियों हजार लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ संभाग के अन्य स्थानों पर कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ संभाग के कृषि श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में मौसमी मजदूरों के रूप में इलाहाबाद होकर अन्य स्थानों को जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस संभाग के लाखों तीर्थयात्री प्रति वर्ष प्रयाग, काशी तथा अयोध्या के तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ आते-जाते हैं। परन्तु खेद का विषय है कि छत्तीसगढ़ संभाग से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार के पश्चिमी भाग को जोड़ने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को छोड़कर कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। और सारनाथ एक्सप्रस सप्ताह में मात्र दो दिन ही चलती है, जिससे उपर्युक्त क्षेत्रों के बीच एक बहुत बड़ी संख्या में आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं गत जून माह में दुर्ग गया था तो बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात की शिकायत की थी।

अतएव मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह अनुरोध करूंगा कि सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाय।

**(ix) Shifting of D.V.C. Headquarters to Bihar.**

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा) : बिहार की जनता, उपेक्षाओं के क्रम में, दामोदर घाटी निगम की उपेक्षा से बड़ी चिंतातुर हो गई है। दामोदर घाटी निगम के स्थापना काल 1964 में बिहार के तत्कालीन विद्युत मंत्री स्व० राम चरित सिंह ने बिहार के विधायकों को आश्वासन दिया था कि निगम मुख्यालय बिहार में होगा। दुर्भाग्यवश इसका मुख्यालय कलकत्ता में चला गया।

वहां जाने पर भी बिहार के क्षतिग्रस्त एवं पीड़ित किसानों की क्षतिपूर्ति घोखाधड़ी में अत्यल्प राशि देकर की गई। निगम के विधान के अनुसार उपाध्यक्ष भी बिहार से नहीं लिया गया। करीब 100,000 जनता विस्थापित हुई तथा लाखों एकड़ कृषि भूमि दामोदर नदी के जलाशयों में जलमग्न हो गई। नौकरियों में प्रभावित लोगों की घोर उपेक्षा हुई। विद्युत आपूर्ति एवं सिंचाई में नगण्य लाभ हुआ।

इस पर बिहार सरकार ने सभी दलों के 24 विधायकों की एक विद्युत परियोजना समिति विपक्षी नेता श्री सुनील मुखर्जी की अध्यक्षता में अप्रैल 73 में गठित की गई। उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार भी डी वी सी ने विद्युत आपूर्ति केन्द्रीय उपक्रमों में व्यय कर बिहार की घोर उपेक्षा की। साथ ही नियोजनों में भी 10-15 भी स्थान नहीं दिए गए।

95 प्रतिशत परियोजनाएं बिहार की धरती पर हैं तथा इसका सभी लाभ बिहार से अन्यत्र

हो रहा है। इस परिस्थिति में आम जनता बराबर धरना, प्रदर्शन एवं अनशन के द्वारा केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई को विधान सभा में विधायकों के समक्ष कहा कि दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों से कहकर मुख्यालय बिहार के माईथाण, हजारी बाग या रांची में लाने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार उपेक्षित जमीन मुख्यालय हेतु अर्जित करने के लिए तैयार है। अतः भारत सरकार से अपील है कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय बिहार में लाकर जनता को उचित न्याय दिलाया जाये। यह जनहित के लिए एक अनिवार्य कदम होगा। (इति)

---

**12.28 Hrs.**

## ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, we shall now take up the Legislative Business—the Electricity (Supply) Amendment Bill.

The time allotted for the Electricity (Supply) Amendment Bill is 4 hours. We have already exhausted 4 hours and 16 minutes. But I would like to give chance to all Members who want to speak. I do not want to stop any Members, let him speak. But I would ask the Members to be as brief as possible because we have already exhsuated the time.

SHRI CHITTA BASU : A good gesture, Sir.

SHRI GEORGE FERNANDES : Sometimes you are a good Deputy-Speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I hope I shall always be.

Now, Mr. Ashfaq Hussain has to continue his speech. But he is absent. So, now Mr. Namgyal may speak.

**श्री पी० नामग्याल** (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 1983 पर बहस चल रही है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल में इसके तरमीम का मकसद बताया गया है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसकी तरमीम करने का मकसद भी बताया है। स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जितनी सरप्लस रेवेन्यू कमाएंगे वह एकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन इसका Quantum of Surplus किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सरप्लस रेवेन्यू में नहीं दिखाई है। इस वजह से इन बोर्डों का आपस में वर्किंग कंपेरीजन करने में मुश्किल होती है। इस बिल में कोई भी इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड तीन परसेंट से ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे तो उसको स्पेसिफाई करना आपने लाजिमी करार दिया है। कमर्शियल एकाउंटिग का जो तरीकेकार है उन्हीं लाइंज पर बोर्डों के एकाउंट्स को लाना आपने इस बिल में लाजिमी करार दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्ज बनाने के अखत्यारात देने की बात कही है।

जहां तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डज की कारकर्दगी का सवाल है, अखबारों में आपको हर रोज पढ़ने को मिलेगा कि हर स्टेट में कहीं न कहीं पावर शैडिंग हुई है। मतलब यह कि इन बोर्ड्ज का जो वर्किंग है वह तसल्लीबख्श नहीं है। परसों की बात है। एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से इस कद्र बिजली ली गई है कि सात स्टेट्स के ऊपर कुल मिला कर तीन सौ करोड़ का बकाया है। इसके इलावा एक स्टेट दूसरी स्टेट से जो भी लेती है। वह अलग है जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट पंजाब और हिमाचल से बिजली लेती है। वह इस में दिखाई नहीं गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड्ज का जो वर्किंग है वह तसल्लीबख्श नहीं है।

आपने इस बिल में तीन परसेंट सरपलस अगर रेवेन्यू होता है तो उसको दिखाना, उसको स्पेसिफाई करना लाजिमी करार दिया है। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। जैसे दूसरे मेंबर साहिबान ने भी प्वाइंट आउट किया कि तीन परसेंट से ज्यादा स्पेसिफाई करने का सवाल ही कहां पैदा होता है जब सारे बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर